सं०ग्रो०वि०/पानी/141-85/24249.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा), करनाल, के श्रमिक श्री शिव चरण, पुत्र श्री गंगादत, बांसा गेट, करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीधोगिक विवाद है ;

धीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेनु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इस लिये, अब, श्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य गल इसके द्वारा सरकारी श्रधिसूचना सं० 3(44)84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अन्त्राला, को विवाद प्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्गय एवं पंचाट , तीन मास में देने हेत् निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अधवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री शिव चरण की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? सं० ग्रो॰वि॰/पानी/142-85/24255.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै॰ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल, के श्रीमिक श्री मान सिंह, पुत्र श्रो सुलेख चन्द, गांव गढ़ी जटान, तह० व जिला करनाल तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछंनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, भौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की घारा 7 के अधीन गठित अमें न्यायालय, अम्बाला, को विवादप्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा अभिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री मान सिंह की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहतका हकदार है ?

सं० थ्रो०वि०/यमुना/ 68-86/24261. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं उन्सन इजिनियर्ज (यमुना गैसिज यूनिट सरदाना नगर) श्रम्बाला रोड़, जगाधरी, के श्रमिक श्री वेद प्रकाश, पुत्र श्री मुन्शी राम, मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा, इन्टक ब्राह्मण धर्मशाला रेलवे रोड़ जगाधरी, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं 0.3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 ग्रप्रैल, 1984, द्वारा उक्त ग्रिधसूचना की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय, ग्रम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा - मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत ग्रथवा सम्बन्धित मामला है :-- "

क्या श्री वेद प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? सं० भ्रो०वि०/यनुना/50-86/24267.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० कुष्णा कापर एण्ड स्टील रोलिंग मिल, कोर्ट, रोड़, जगाधरी के श्रमिक श्री विजय कुमार, मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा, शहमण धर्मशाला रेलवे रोड़, जगाधरी तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीशोगिक विवाद है ;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं :

इसलिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री विजय कुमार, पुत्र श्री चमन लाल की सेवा समाप्त की गई है या वह स्वयं नौकरी से अनुपस्थित हो रहा है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है?